

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 216/2017/225 आर टी ए

रामजस पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़।

---अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

--- रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20.06.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया

प्र०सं० 136/2016 बअनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि

उपस्थित :-

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट 2

निर्णय

दिनांक:-18.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प रतनपुरा के पेश होने का कथन किया तथा मौके से जांच रिपोर्ट तलब करने का कथन कर चक 3 एमजेडी तहसील संगरिया के प.न. 171/182 के मु. न. 36 कि.न. 2 में 0.015 है० डीएलसी की दुगुनी राशि जमा कराये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंका करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत एवं विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि चक 3 एमजेडी के प.न. 171/182 मु.न. 36 कि.न. 2/0.015 है० रास्ता जिस जगह पर

स्वीकृत किया गया है, वहां पर अपीलांट के खेजडी का बड़ा वृक्ष है यदि उस स्थान पर रास्ता चालू कर दिया जाता है तो अपीलांट का खेजडी का वृक्ष नष्ट हो जायेगा जिससे अपीलांट को भारी नुकसान होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 148/2016 अनवानी विजय सिंह बनाम धर्मपाल आदि प्रस्तुत हुआ जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2017 को चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि में अपीलांट की भी 2 बीघा भूमि थी उसमें भी रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पों सं. 1 ने जिस भूमि लिए रास्ता का अनुतोष चाहा गया है, उस भूमि के चिपते हुए प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है और रेस्पों सं. 1 की भूमि के लिए उक्त पर्याप्त रास्ता है तो अपीलांट की भूमि में पृथक से मुरब्बा न. 36 के कि.न. 2 में रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट की भूमि में अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों तरफ रास्ता स्वीकृत कर दिया है। अपीलांट एक लघु कृषक है जिससे उसकी बेकीमती भूमि रास्ते में दोनों तरफ अनावश्यक चली जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प रतनपुरा में पारित किया है। राजस्व लोक अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति से तथा मुताबिक राजीनाम आदेश पारित किया जाना चाहिए था ताकि आईन्दा से पक्षकारों के मध्य कोई विवाद ना हो परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर उक्त आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की कर प्रार्थना पत्र संख्या 136/2016 अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.17 को अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पों ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पों सं. 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर चक 3 एमजेडी तहसील संगरिया के प.न. 171/182 के मु.न. 36 कि.न. 2 में 0.015 है० स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता होने के कथन किये गये हैं वह रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पों को अपनी खातेदारी भूमि रास्ता की परम

आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए रास्ता स्वीकार किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।
6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो० सं. 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर चक 3 एमजेडी तहसील संगरिया के प.न. 171/182 के मु.न. 36 कि.न. 2 में 0.015 है० रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प में अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। जबकि प्रश्नगत रास्ता जिस भूमि जगह पर स्वीकृत किया गया है उस रास्ते के बीच में एक खेजड़ी का पेड़ है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट है तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 148/2016 अनवानी विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2017 को चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि में अपीलांट की भी 2 बीघा भूमि थी उसमें भी रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पो० सं. 1 ने जिस भूमि लिए रास्ता का अनुतोष चाहा गया है, उस भूमि के चिपते हुए प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है और रेस्पो० सं. 1 की भूमि के लिए उक्त पर्याप्त रास्ता है तो अपीलांट की भूमि में पृथक से मुरब्बा न. 36 के कि.न. 2 में रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट की भूमि में अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों तरफ रास्ता स्वीकृत कर दिया है। इस प्रकार अपीलांट की भूमि के दोनों तरफ रास्ते स्वीकृत किये गये हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों (अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस एवं अनवानी विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि) में एक साथ मौका की जांच के आधार पर दोनों ही पत्रावलियों में रास्ता की आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए रास्ते स्वीकृत किये जाने चाहिए थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। जबकि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अपीलांट सहमत नहीं था इसके बावजूद भी अपीलांट को अपने पक्ष रखने बाबत कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा

अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही रास्ता के प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 136/2016 अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि एवं प्रकरण संख्या 148/2016 दोनों प्रकरणों में एक साथ उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत दोनों प्रकरणों में एक साथ पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़